



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2019/चैत्र 6, 1941

No. 99]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2019/CHAITRA 6, 1941

नीति आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

फा. सं. 1/5/2019-टीपीटी / एनआईटीआई.—1. (i) सं. राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण मिशन की स्थापना के लिए 7 मार्च 2019 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा "एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति के साथ "राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण मिशन" का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः:-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| i. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग | - | अध्यक्ष |
| ii. | सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | - | सदस्य |
| iii. | सचिव, विद्युत मंत्रालय | - | सदस्य |
| iv. | सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | - | सदस्य |
| v. | सचिव, भारी उद्योग विभाग | - | सदस्य |
| vi. | सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | - | सदस्य |
| vii. | सचिव, उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | - | सदस्य |
| viii. | महानिदेशक, औद्योगिक मानक ब्यूरो। | - | सदस्य |

यह मिशन नीति आयोग में स्थापित किया जाएगा और नीति आयोग के परिवहन (इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी) वर्टिकल द्वारा सेवित होगा।

मिशन के विचारार्थ विषय

मिशन के विचारार्थ विषय निम्नांकित हैं:

- i. संचालन समिति के निर्णयों और सिफारिशों का कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करना।
 - ii. भारत में समग्र, संधारणीय और परिवर्तनशील गतिशीलता और ऊर्जा भंडारण के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों और सरकारी अंतःक्षेपों तथा संभावित कार्यनीतियों का प्रस्ताव और सिफारिश करना।
 - iii. अपेक्षित मुख्य अंतःक्षेपों, प्रोत्साहनों और परियोजनाओं का विश्लेषण और प्रस्ताव करना। साथ ही, परिवर्तनकारी गतिशीलता और ऊर्जा भंडारण की दिशा में नोडल एजेंसी/मंत्रालय के लिए प्राथमिकता निर्धारित करना और इसके कार्यान्वयन हेतु सिफारिश करना। इसके अतिरिक्त, इन अंतःक्षेपों/परियोजनाओं के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करना।
 - iv. वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उद्योग हेतु संपूर्ण पारितंत्र विकसित करने के उद्देश्य से पूरी इलेक्ट्रिक वाहन मूल्य श्रृंखला में उत्पादन को स्थानिक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहन संघटकों हेतु एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) तैयार करना और आरंभ करना। यह सुनिश्चित करेगा कि उदीयमान प्रौद्योगिकियों के लिए घटक स्तर के स्वदेशी विनिर्माण को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाए और उच्च क्षमता वाले उद्योग के विकास को कोई नुकसान न हो।
- (v) वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में बैटरी सेलों का लगभग 35% हिस्सा होता है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसे नई और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ग्रिड स्थिरीकरण और उपकरणों की बढ़ती संख्या को पूरा करते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ऊर्जा भंडारण समाधानों की अत्यधिक आवश्यकता है। मिशन द्वारा कच्चे माल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट, जिसमें सेल, मॉड्यूल, बैटरी पैक का निर्माण और वाहनों में उपयोग शामिल है, सहित बैट्रियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) तैयार और आरंभ किया जाएगा। इसके लिए उद्योग की सक्रिय भागीदारी के साथ गीगा पैमाने पर विनिर्माण की आवश्यकता होगी।
- (vi) विभिन्न हितधारकों नामतः भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों, उद्योग, शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों आदि के प्रयासों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए नियमित विचार-विमर्श करना। इसके अलावा बाधाओं, यदि कोई हो, का समन्वय और समाधान करना।
- (vii) परिवर्तनकारी गतिशीलता और ऊर्जा भंडारण संबंधी मिशन, इसके उद्देश्यों, मात्रात्मक परिणामों और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं के संबंध में अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना और रूपरेखाओं की जांच, निर्माण, प्रस्ताव और संचालन करना।
- (viii) संचालन समिति की सिफारिश पर भारत में समग्र, संधारणीय और परिवर्तनकारी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए किसी भी कानून, अधिनियम या अधिसूचना को प्रस्तुत करने या किसी मौजूदा कानून, अधिनियम या अधिसूचना में संशोधन करने संबंधी मामलों की जांच करना और मंत्रिपरिषद / मंत्रिमंडल को प्रस्तावित करना।
- (ix) इसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

अनिल श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार

**NITI AAYOG
NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th March, 2019

F. No. 1/5/2019-Tpt/NITI .—1.(i).—No. In pursuance of the decision of the Cabinet in its meeting held on 7th March, 2019 for setting up the **National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage**, the Central Government hereby constitutes the “**National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage**” with an Inter-Ministerial Steering Committee, comprising of the following members, namely:

- | | | | |
|-------|--|---|----------|
| i. | CEO, NITI Aayog | - | Chairman |
| ii. | Secretary, Ministry of Road Transport and Highways | - | Member |
| iii. | Secretary, Ministry of Power | - | Member |
| iv. | Secretary, Ministry of New and Renewable Energy | - | Member |
| v. | Secretary, Department of Heavy Industry | - | Member |
| vi. | Secretary, Department of Science and Technology | - | Member |
| vii. | Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade | - | Member |
| viii. | Director General, Bureau of Industrial Standards. | - | Member |

The Mission, would be housed in NITI Aayog and served by the Transport (Infrastructure Connectivity) Vertical of NITI Aayog.

Terms of Reference of the Mission

The terms of reference of the Mission are as follows:

- i. Ensure implementation and compliance of the decisions and recommendations of the Steering Committee.
- ii. Propose and recommend policy guidelines and government interventions and possible strategies for holistic, sustainable and transformative mobility and energy storage in India.
- iii. Analyse and propose the key interventions, incentives and projects required. Also prioritise and recommend the same towards transformative mobility and energy storage, to the nodal agency/ministry for its implementation. Additionally, plan the short-term and long-term road map for these interventions/projects.
- iv. To formulate and launch a Phased Manufacturing Program (PMP) for EVs & EV Components to localize production across the entire EV value chain, in order to develop the entire eco-system for industry to achieve global competitiveness. It will ensure that adequate time is provided to develop the component level indigenous manufacturing for nascent technologies and prevent any setback to the growth of the high-potential industry.
- v. Battery cells currently constitute around 35% of the cost of electric vehicles. India is the fastest growing economy in the world with a huge requirement for energy storage solutions for electric mobility, complementing new and renewable energy generation, grid stabilization and the growing number of devices. Mission is to formulate and launch a Phased Manufacturing Program (PMP) focussing on batteries including raw materials, electrochemistry, end of life treatment, comprising manufacture of cells, modules, battery packs and usage in vehicles. This would require manufacturing at Giga scale with active participation of the industry.
- vi. Hold regular deliberations to ensure synergy amongst the efforts of various stakeholders namely; Government of India Ministries/Department, state Governments, industry, academia, research institutes etc. Also co-ordinate and resolve road blocks if any.
- vii. Examine, formulate, propose and drive the short-term and long-term plan and contours of the mission on transformative mobility and energy storage, its objectives, quantifiable outcomes and roles of various stakeholders.
- viii. Examine and propose to the Council of Ministers/Cabinet the introduction of any legislation, act or notification or amendment to an existing legislation, act or notification for promoting holistic, sustainable and transformative mobility in India upon the recommendation of the Steering Committee.
- ix. Any other task assigned to it.

ANIL SRIVASTAVA, Principal Adviser